उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सूभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 12 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(09/62)

बुधवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में आपदा प्रबंधन पर राज्य स्तरीय एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पन्त द्वारा ''डिजास्टर रिस्क एसेसमेंट डाटा बेस'' लांच किया गया।

वित्त मंत्री श्री पंत द्वारा आपदा प्रबन्धन चक्र के महत्वपूर्ण बिन्दु न्यूनीकरण, पुनर्वास, आपदा जोखिम, रिकवरी पर विशेष बल दिए जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इसे कम से कम किये जाने का प्रयास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विभागों को इससे जोड़ा जाएगा, ताकि अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रों के निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन कार्य को किया जा सके। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के बाद भी हम मानव हानि को रोकने में काफी हद तक सफल हुए है, जो कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन की तैयारियों के कारण संभव हो पायी है। उन्होंने कहा कि अनियोजित निर्माण कार्य रोकने के लिये डिजास्टर रिस्क डाटा बेस को सभी विभागों की कार्ययोजना में शामिल किया जायेगा, जिससे आपदा न्यूनीकरण में सहायता मिल सकेगी।

सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित सिंह नेगी ने कहा कि डिजास्टर रिस्क एसेसमेंट डाटा बेस के अन्तर्गत भूकम्प, भूस्खलन एवं अन्य दैवीय आपदाओं के प्रति संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित् किया गया है, जिसके अनुसार ही रिस्क डेटा बेस को तैयार किया गया है जिसका उपयोग सरकार की भविष्य की नीतियों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक बहेतरीन कदम है आपदा जोखिम एवं न्यूनीकरण की ओर बढ़ने का।

सदस्य एन.डी.एम.ए. भारत सरकार श्री कमल किशोर, तथा अधिशासी निदेशक, एन.आई.डी.एम भारत सरकार श्री अनिल कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये। जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड देश का तीसरा ऐसा राज्य है, जिसने आपदा के परिपेक्ष में डिजास्टर रिस्क डेटाबेस को तैयार किया गया है, जो उत्तराखण्ड सरकार तथा जन मानस के लिए काफी उपयोगी रहेगा।

टीम लीडर डीएचआई, सिंगापुर जेवी विद् एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नालॉजी, थाईलैंड एण्ड ई.आर.एन., मैसिको श्री टॉम बक्रुट द्वारा प्रतिभागियों को अध्ययन के विषयगत अवगत कराया गया तथा इस अध्ययन में उपयोग में लाए गए डाटा तथा टूल (कैपरा) के बारे में बताया गया एवं उनसे प्राप्त परिणाम से परिचित कराया गया। उनके द्वारा उक्त अध्ययन को पूर्ण कराये जाने में किन–किन चुनौतीयों का सामना करना पड़ा उससे अवगत कराया गया।

ई.आर.एन. मैक्सिकों के डॉ.एडवार्डों रेनीसियो, ए.आई.टी के डॉ.मंजूल कुमार, डी.एच.आई. सिंगापुर के डॉ.जुलियन ओलीवर तथा आई.आई.टी के डॉ.एम.एल.शर्मा द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये।

अपर सचिव आपदा प्रबन्धन श्री सविन बंसल द्वारा उक्त अध्ययन की उपयोगिता से अवगत कराते हुए सभा का धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

विश्व बैंक द्वारा पोषित, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन, उत्तराखण्ड आपदा पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत गठित कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, तकनीकी सहायता व क्षमता विकास के घटक डिजास्टर रिस्क एसेसमेंट ऑफ उत्तराखण्ड स्टडी का कार्य मई, 2016 से गतिमान अवस्था में है। जिसे फर्म डीएचआई, सिंगापुर जेवी विद् एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नालॉजी, थाईलैंड एण्ड ई.आर.एन., मैसिको के माध्यम से सम्पन्न किया जा रहा है।

इस अध्ययन के अन्तर्गत भौगोलिक सूचना तंत्र (जियोग्राफिक इंर्फोमेंशन सिस्टम प्लेटफार्म)' पर विभिन्न आपदाओं जैसे भूकम्प, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित बाढ़ तथा औद्योगिक के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड राज्य का विस्तृत डाटा बेस तथा विभिन्न प्रकार के मॉडलों के माध्यम से विश्लेषण किया गया है। उक्त समस्त डाटा बेस जो कि डिजीटल रिस्क डाटा बेस (डी. आर.डी.बी.) है यह वेब आधारित है इसके माध्यम से राज्य में आपदा के समय त्वरित निर्णय लिये जाने एवं डीसीजन सर्पोट सिस्टम तैयार किए जाने हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक श्री दिलीप सिंह रावत, अपर सचिव डॉ.वी. षणमुगम, निदेशक आपदा प्रबंधन डॉ.पीयूष रौतेला तथा मौसम विभाग के निदेशक श्री विक्रम चौहान, भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार/संस्थानों/शिक्षण संस्थानों जैसे आई.आई.आर.एस., वाडिया भूविज्ञान संस्थान, आई.एम.डी, आई.आई.टी, सी. बी.आर.आई, आई.आर.आई., लो.नि.वि., सिंचाई विभाग, डी.एम.एम.सी आदि के लगभग 150 विषय विशेषज्ञों/उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 12 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(09/61)

जिला चिकित्सालय पौड़ी में वरिष्ठ फिजीशियन की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया।

वरिष्ठ फिजीशियन डॉ.अमित रौतेला का हल्द्वानी से जिला चिकित्सालय पौड़ी स्थानान्तरित किये जाने पर पौड़ी के विधायक श्री मुकेश कोली ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। पौड़ी में स्थानीय जनता द्वारा लम्बे समय से वरिष्ठ फिजीशियन की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक श्री मुकेश कोली के अनुरोध पर जनहित में जिला चिकित्सालय पौड़ी में एक वरिष्ठ फिजीशियन को नियुक्त करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये। स्वास्थ्य विभाग ने जनहित में डॉ. अमित रौतेला का स्थानान्तरण हल्द्वानी से पौड़ी किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियों को पार पाने की कोशिश की गई है। हाल ही में राज्य में एक हजार डॉक्टरों की तैनाती की गयी है, इनमे से ज्यादातर डॉक्टरो को पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा गया है। उत्तराखण्ड की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रदेश के सभी 22 लाख परिवारों के सालाना 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च अब सरकार उठाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 43 अस्पतालों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। टेली रेडियोलॉजी के माध्यम से सूदूरवर्ती 35 मेडिकल सेंटर में एक्स–रे, सी.टी.स्कैन, एम.आर.आई. व मेमोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 6 स्वास्थ्य केन्द्रों में ई–हेल्थ सेंटर स्थापित करते हुए तमाम तरह की जांच सुविधा दी जा रही है। सभी जिला अस्पतालों में आई.सी.यू. की स्थापना पर भी काम शुरू कर दिया गया है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में पहला आईसीयू स्थापित हो चुका है। जनसामान्य को सस्ती दवाऐं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत 100 जन औषधि केन्द्रों के सापेक्ष 106 केंद्र खोले गए हैं। इसके अलावा 100 अतिरिक्त जन–औषधि केंद्रों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

देहरादून 12 सितम्बर, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(09/60)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में बिहारी महासभा के प्रतिनिधिमण्डल ने शिष्टाचार भेंट की।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।